पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजू कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2025 का आपराधिक विविध संख्या 15800

10 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ की कम मात्रा से कम मात्रा से जुड़े अपराध जमानती प्रकृति के हैं या नहीं?

हेडनोट्स

एनडीपीएस अधिनियम---धारा 21(ए), 21(सी), 37----एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानती अपराध---- याचिकाकर्ताओं के कब्जे से मादक पदार्थ की कम मात्रा से कम मात्रा बरामद होने के आरोप पर जमानत के लिए याचिका।

निर्णय:- चूंकि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा निर्विवाद रूप से छोटी है, इसलिए प्राथमिकी एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21(सी) के बजाय धारा 21(ए) के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी--- इस संबंध में एक प्रचलित गलत धारणा के बावजूद, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं---जबकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, यह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता है कि सभी अपराध गैर-जमानती हैं---यदि विधायिका का अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती के रूप में नामित करने का इरादा था, तो यह स्पष्ट रूप से यह कहकर ऐसा कर सकता था कि सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती दोनों हैं----एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत छोटी मात्रा वाले अपराध जमानतीय है, इसलिए जमानत का अधिकार वैधानिक अधिकार का मामला है और ऐसी परिस्थिति में पुलिस या न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार

उपलब्ध नहीं है----डीजीपी, बिहार को अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया की जहां बरामद प्रतिबंधित पदार्थ कम मात्रा में है, अपराध जमानतीय है और संदिग्ध जमानत का हकदार है। (पैरा- 10, 12, 25, 27)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023---धारा 4, 5---एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे में बीएनएसएस की प्रयोज्यता----जमानती और गैर-जमानती अपराधों का वर्गीकरण----विशेष अधिनियमों सहित किसी भी कानून के तहत अपराध, बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जब तक कि विशेष क़ानून स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न करे----एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों का जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकरण आवश्यक रूप से बीएनएसएस, 2023 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए----बीएनएसएस, 2023 व्यापक प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते, विशेष कानूनों के तहत होने वाली कार्यवाही सहित सभी आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसे विशेष क़ानूनों में विशिष्ट प्रावधान हों जो सामान्य ढांचे को ओवरराइड या संशोधित करते हों-----एनडीपीएस में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत कुछ गंभीर अपराधों के लिए बनाए गए विशिष्ट अपवादों के अधीन, जमानत के संबंध में बीएनएसएस, 2023 के सामान्य प्रावधान ऐसे मामलों को नियंत्रित करना जारी रखेंगे - एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (ए) के तहत अपराध, जो एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ दंड निर्धारित करता है, बीएनएसएस, 2023 के तहत वर्गीकरण के अनुसार जमानतीय अपराध के दायरे में आता है - एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 (ए) के तहत छोटी मात्रा से जुड़े अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति बीएनएसएस, 2023 की धारा 478 (1) के प्रावधानों के अनुसार कानून के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर तुरंत जमानत पर रिहा होने का हकदार है। (पैरा 15, 16)

न्याय दृष्टान्त

अब्दुल अजीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2002 एससीसी ऑनलाइन एआईआई **1223;; स्टीफन मुलर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010** एससीसी ऑनलाइन बॉम **1974; राज कुमार बनाम राजस्थान राज्य 2019** एससीसी ऑनलाइन राज **5732; मुहम्मद नवास महमूद बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर, 2020** एससीसी ऑनलाइन केर **564-पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

एनडीपीएस अधिनियम; छोटी मात्रा से कम की बरामदगी; एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानती अपराध; बीएनएसएस, 2023 के तहत जमानती और गैर-जमानती के रूप में अपराध का वर्गीकरण; विशेष कानून के तहत अपराधों का परीक्षण; संज्ञेय अपराध।

प्रकरण से उत्पन्न

मुफ्फसिल थाना केस संख्या 13/2025 में विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(आपराधिक विविध संख्या 15800/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: सुश्री वैष्णवी सिंह, न्यायमित्र; श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी/पक्षियों के लिए: श्री चौबे जवाहर, एपीपी; सुश्री रेणु कुमारी, एपीपी; श्री नंद किशोर प्रसाद, एपीपी

(आपराधिक विविध संख्या 18113/2025 में)

याचिकाकर्ता/पक्षियों के लिए: श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी/पक्षियों के लिए: श्री नित्या नंद तिवारी, एपीपी; श्री संजय कुमार तिवारी, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या 15800 वर्ष 2025

थाना कांड संख्या -13 वर्ष-2025 थाना- कटिहार मुफस्सिल जिला- कटिहार से उत्पन्न

==========

राजू कुमार, पुत्र गंगा प्रसाद, निवासी सिरसा, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

..... विपक्षी पक्ष

==========

साथ में

आपराधिक विविध संख्या 18113 वर्ष 2025

थाना कांड संख्या-1 वर्ष-2025 थाना-बलिया बेलौन जिला-कटिहार से उत्पन्न

==========

रोशन कुमार उर्फ रौशन कुमार दास पुत्र मनोज कुमार दास निवासी ग्राम- ढांगी, थाना-बलिया बेलोन, जिला-कटिहार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....विपक्षी पक्ष

==========

उपस्थिति :

(आपराधिक विविध संख्या 15800/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : सुश्री वैष्णवी सिंह, न्यायमित्र

श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी/ओं की ओर से : श्री चौबे जवाहर, एपीपी

सुश्री रेणु कुमारी, एपीपी

श्री नंद किशोर प्रसाद, एपीपी

(आपराधिक विविध संख्या 18113/2025 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी/ओं की ओर से : श्री नित्या नंद तिवारी, एपीपी

श्री संजय कुमार तिवारी, एपीपी

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रूद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक आदेश

10.04.2025

वर्तमान आवेदन अर्थात आपराधिक विविध संख्या 15800/2025, याचिकाकर्ता को मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 13/2025 के संबंध में जमानत देने के लिए दायर किया गया था, जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम') की धारा 8(बी) और 21(सी) के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है। वर्तमान मामले में, 0.19 ग्राम स्मैक और 6.56 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जो निश्चित रूप से छोटी मात्रा के दायरे में आता है, लेकिन एन.डी.पी.एस. की धारा 21(सी) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि बरामदगी कम मात्रा में हुई है। *प्रथम दृष्टया,* इस न्यायालय का विचार था कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21(ए) के तहत अपराध प्रकृति में जमानती है, ऐसे में

याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा ही जमानत दी जानी चाहिए थी, हालांकि, याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा जमानत नहीं दी गई और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी याचिकाकर्ता की जमानत खारिज कर दी। इस प्रकार, इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2025 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को जमानत दे दी, लेकिन कानून के प्रावधानों की बेहतर समझ के लिए मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया। बाद में, आपराधिक विविध संख्या 18113/2025, जो वर्तमान मामले के समान है, को भी आपराधिक विविध संख्या 15800/2025 के साथ आज के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

2. इससे पहले दिनांक 20.03.2025 के आदेश के तहत श्रीमती वैष्णवी सिंह को इस न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया गया था।

3. इन दोनों मामलों में बरामदगी कम मात्रा में हुई है, लेकिन सुविधा के लिए यह न्यायालय आपराधिक विविध संख्या 15800/2025 से तथ्य लेगा।

4. राज्य के विद्वान न्यायमित्र और विद्वान एपीपी को सुना गया।

5. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कुल 0.19 ग्राम स्मैक और 6.56 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसमें से याचिकाकर्ता से 1.57 ग्राम गांजा और एक मोबाइल बरामद किया गया, जबकि सह-आरोपी विष्णु कुमार से 0.19 ग्राम स्मैक और 4.99 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

6. विद्वान न्यायमित्र ने दलील दी है कि चूंकि इस मामले में बरामदगी कम मात्रा में हुई है, इसलिए एफआईआर धारा 21(सी) के बजाय नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस एक्ट') की धारा 21(ए) के तहत दर्ज की जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 का शीर्षक बताता है कि *"अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होने*

चाहिए", लेकिन इसमें सभी अपराधों का उल्लेख नहीं है। शीर्षक में *"सभी"* शब्द को जानबूझकर छोड़ना विधानमंडल की मंशा को दर्शाता है। धारा के भीतर ही, *"प्रत्येक"* शब्द खंड (1)(ए) में दिखाई देता है, और इसका स्थान उद्देश्यपूर्ण है। अधिनियम अपराधों को वर्गीकृत करता है और मादक दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों की मात्रा के आधार पर दंड निर्धारित करता है - छोटी, मध्यम और वाणिज्यिक मात्रा। यदि विधानमंडल का इरादा *सभी* अपराधों को गैर-जमानती बनाने का होता, तो उसने शीर्षक में ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहा होता। इस तरह के शब्दों का अभाव अन्यथा सुझाव देता है। वह आगे कहती हैं कि *सभी* अपराधों को गैर-जमानती बनाने से इस मात्रा-आधारित वर्गीकरण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक छोटी मात्रा (संभवतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए) के कब्जे को एक वाणिज्यिक मात्रा के कब्जे के बराबर मानने से वही कठोर परिणाम होंगे, अपराध की गंभीरता या संदर्भ की परवाह किए बिना लंबे समय तक कारावास। यह दृष्टिकोण कानून के पुनर्वास के इरादे को कमजोर करेगा, खासकर उपयोगकर्ताओं, नशेड़ी या कम मात्रा में पाए जाने वाले लोगों के लिए। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 39 और 64 ए सजा पर उपचार को प्राथमिकता देने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करती है, कार्यान्वयन प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और नशामुक्ति और पुनर्वास पर अधिक जोर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने धारा 37 को एक अंतर को दर्शाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया है। जबकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि *सभी* अपराध संज्ञेय हैं, यह इसी तरह घोषित नहीं करता है कि *सभी* अपराध गैर-जमानती हैं। यह चयनात्मक उपयोग स्पष्ट रूप से कुछ श्रेणियों- विशेष रूप से मामूली अपराधों- को गैर-जमानती के रूप में माना जाने से बाहर करने के विधायी इरादे को दर्शाता है। इस प्रकार, धारा 37 के ऑपरेटिव भाग के भीतर *"सभी अपराध गैर-जमानती हैं"* शब्द का लोप जानबूझकर

और महत्वपूर्ण है। यह नशीली दवाओं के अपराधों की गंभीरता को पुनर्वास और आनुपातिक दंड की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के उद्देश्य से एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस संबंध में, उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है जो इस प्रकार हैं:

(i) अब्दुल अजीज बनाम यू.पी. राज्य, 2002 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 1223

(ii) ***शाजी बनाम केरल राज्य, 18 नवंबर 2003*** को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा तय किया गया।

(iii) स्टीफन म्यूएलर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम 1974

(iv) राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा ए***स.बी. सीआर. विविध जमानत आवेदन संख्या 12786/2019 में पारित दिनांक 23.09.2019*** का आदेश।

7. राज्य के विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि दोनों मामलों में याचिकाकर्ता से कम मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था, हालांकि, धारा 37 के शीर्षक में कहा गया है कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

8. इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों का अध्ययन किया है।

9. इस मामले में बरामद पदार्थ और एनडीपीएस अधिनियम की तालिका के अनुसार छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए उनका वर्गीकरण निम्नानुसार है:

बरामद पदार्थ-

पदार्थ का नाम	गांजा
एनडीपीएस तालिका में **सीरियल नंबर एस.ओ. 1055 (ई), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, धारा में प्रकाशित 3(ii), संख्या 773, दिनांक 19 अक्टूबर 2001.**	55
हिरासत में ली गई मात्रा	6.56 ग्राम
मात्रा का प्रकार	छोटी मात्रा से कम
छोटी मात्रा	**1 किलोग्राम**
वाणिज्यिक मात्रा	20 किलोग्राम

पदार्थ का नाम	स्मैक (हेरोइन)
एनडीपीएस में सीरियल नंबर तालिका **एस.ओ. 1055(ई), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, धारा में प्रकाशित 3(ii), संख्या 773, दिनांक 19 अक्टूबर 2001**	56
हिरासत में ली गई मात्रा	0.19 ग्राम
मात्रा का प्रकार	छोटी मात्रा से कम
छोटी मात्रा	**5 ग्राम**
वाणिज्यिक मात्रा	250 ग्राम

10. प्रतिबंधित पदार्थ यानी 0.19 ग्राम स्मैक और 6.56 ग्राम गांजा की मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है, जो निर्विवाद रूप से छोटी मात्रा है, इसलिए, एफआईआर को उक्त अधिनियम की धारा 21(सी) के बजाय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(ए) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(ए) के तहत अपराध के लिए जो सजा निर्धारित की गई है, वह कठोर

कारावास है जो एक वर्ष तक या जुर्माना हो सकता है जो 10,000/- रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। जहां तक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 का सवाल है, इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि अधिनियम के तहत *सभी* अपराध गैर-जमानती हैं। इस संबंध में प्रचलित गलत धारणा के बावजूद, प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी व्याख्या निराधार है।

11. प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान जैसे एन.डी.पी.एस. की धारा 36ए, धारा 37। अधिनियम की धारा

> *" **36ए. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध.-***
>
> *(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,-*
>
> *(क) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं, केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, वहां उनमें से किसी एक द्वारा, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।*
>
> *(ख) xxxxxxx*
>
> *(ग) xxxxx*
>
> *(घ) xxxx*
>
> *(2) xxxx*
>
> *(3) xxxx*
>
> *(4) xxxx*

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षेप में विचारण किया जा सकेगा।

इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई अपराध जिसमें सजा तीन वर्ष से अधिक है, तो वह विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है और जहां कोई अपराध जिसमें सजा तीन वर्ष से कम है, वह बी.एन.एस.एस., 2023 की पहली अनुसूची के भाग-II में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। "

37. अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना *-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, -*

(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत दंडनीय अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी आरोपी किसी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि--

(i) सरकारी अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

12. उपरोक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 का शीर्षक यह बताता है कि *अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती* होने चाहिए, धारा का मूल पाठ अन्यथा प्रदान करता है। विशेष रूप से, जबकि प्रावधान स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, यह स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता है कि *सभी* अपराध गैर-जमानती हैं। यदि विधानमंडल का इरादा अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती के रूप में नामित करने का था, तो वह स्पष्ट रूप से यह बताकर ऐसा कर सकता था कि सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती दोनों हैं। इसके बजाय, धारा को सभी अपराधों को संज्ञेय बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जबकि केवल निर्दिष्ट श्रेणी के अपराधों के लिए कठोर जमानत शर्तें निर्धारित की गई हैं - विशेष रूप से वे जो *वाणिज्यिक मात्रा* में तस्करी करते हैं, या धाराओं के तहत दंडनीय अपराध हैं। अधिनियम की धारा 19, 24 और 27ए के अनुसार, जमानत देने पर धारा 37(1) (बी) विशिष्ट और कठोर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें कहा गया है कि इन अपराधों के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत या अपने स्वयं के बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि सरकारी अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है और जहां सरकारी अभियोजन पक्ष आवेदन का विरोध करता है, अदालत को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए आरोपी द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, धारा 37(2) इन सीमाओं को और मजबूत करते

हुए यह निर्धारित करती है कि धारा 37(1)(बी) में निर्धारित प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (पुरानी सीआरपीसी) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 या लागू किसी अन्य कानून के तहत जमानत के लिए सामान्य शर्तों के *अतिरिक्त* लागू होंगे।

13. **"फ्रिक इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ" और अन्य** में **"(1990) 1 एससीसी 400"** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> *"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धाराओं या प्रविष्टियों के आगे लगाए गए शीर्षक प्रावधानों के स्पष्ट शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं; उन्हें प्रावधान की व्याख्या करने के उद्देश्य से भी संदर्भित नहीं किया जा सकता है जब प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हों; न ही उन्हें प्रावधान में शब्दों के स्पष्ट अर्थ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल अस्पष्टता या संदेह के मामले में, शीर्षक या उप-शीर्षक को प्रावधान को बाधित करने में सहायता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले में भी इसका उपयोग प्रावधानों में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों के व्यापक अनुप्रयोग को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"*

14. हालांकि, वर्तमान मामले में, एन.डी.पी.एस. की धारा 37 का मुख्य भाग अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, हालांकि, यह अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को गैर-

जमानती बनाने का प्रावधान नहीं करता है। यदि विधानमंडल अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध को गैर-जमानती बनाना चाहता था, तो उसने धारा के मुख्य भाग में इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करके ऐसा किया होता और ऐसा करने में चूक को अनजाने में की गई चूक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह माना जाता कि यह जानबूझकर की गई चूक है, जिससे विधानमंडल का इरादा प्रत्येक अपराध को गैर-जमानती नहीं बनाने का है।

15. अब यह न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएसएस, 2023") की प्रासंगिक वैधानिकता पर विचार करेगा। बीएनएसएस, 2023 की धारा 4 इस प्रकार है:-

> ***"4. भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का परीक्षण-***
>
> *1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, विचारण और अन्यथा इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।*
>
> *2. किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, विचारण और अन्यथा उसी प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, जांच, विचारण या अन्यथा निपटान के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन।"*

बीएनएसएस, 2023 की धारा 5 में आगे इस प्रकार प्रावधान है:-

> *"5. **व्यावृत्ति**- इस संहिता में निहित कोई भी बात, इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, वर्तमान में लागू किसी विशेष*

या स्थानीय कानून, या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति, या निर्धारित किसी विशेष प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी।

16. उपर्युक्त प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी कानून के अंतर्गत अपराध, जिसमें विशेष अधिनियम भी शामिल हैं, बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जब तक कि विशेष क़ानून स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान न करे। वर्तमान मामले में, जैसा कि पूर्वगामी चर्चा में स्पष्ट किया गया है, एन.डी.पी.एस. अधिनियम स्पष्ट रूप से यह घोषित नहीं करता है कि अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का *जमानती या गैर-जमानती* के रूप में वर्गीकरण आवश्यक रूप से बीएनएसएस, 2023 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। बीएनएसएस, 2023 एक व्यापक प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते, सभी आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है- जिसमें विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियाँ भी शामिल हैं- सिवाय इसके कि ऐसे विशेष क़ानूनों में विशिष्ट प्रावधान हों जो सामान्य ढांचे को ओवरराइड या संशोधित करते हों। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनुसार सभी अपराध गैर-जमानती हैं, जमानत के संबंध में बी.एन.एस.एस., 2023 के सामान्य प्रावधान ऐसे मामलों को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, जो कुछ गंभीर अपराधों के लिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत बनाए गए विशिष्ट अपवादों के अधीन हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बी.एन.एस.एस., 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में यह प्रावधान है कि तीन वर्ष से कम कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय कोई भी अपराध जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 में किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि

अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं, बी.एन.एस.एस., 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में उल्लिखित सामान्य सिद्धांत एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू होंगे। परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि एन.डी.पी.एस. की धारा 21(ए) के तहत अपराध। अधिनियम- जिसमें एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान है- बीएनएसएस, 2023 के तहत वर्गीकरण के अनुसार जमानती अपराध के दायरे में आता है।

16. जमानती अपराध को बीएनएसएस, 2023 की धारा 2(सी) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

> *"2(सी):- **"जमानती अपराध"** का अर्थ है ऐसा अपराध जिसे प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दर्शाया गया है या जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है; और "गैर-जमानती अपराध" का अर्थ है कोई अन्य अपराध;*

इस प्रकार बीएनएसएस, 2023 की धारा 2(सी) के अनुसार, केवल वे अपराध ही 'जमानती अपराध' की श्रेणी में आएंगे जो बीएनएसएस, 2023 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं या जिन्हें किसी भी कानून के तहत विशेष रूप से 'जमानती अपराध' घोषित किया गया है। विशेष क़ानून के अनुसार, शेष सभी अपराध 'गैर-जमानती' माने जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में भी यही स्थिति थी, जिसे बीएनएसएस, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इस प्रकार, सभी अपराध 'गैर-जमानती' होंगे, जब तक कि उन्हें 'जमानती' के रूप में नहीं दिखाया और निर्दिष्ट नहीं किया जाता।

17. अब, यह न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करेगा। ***अब्दुल अजीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2002 एससीसी***

ऑनलाइन ऑल 1223 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 2, 8, 9 और 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

> *"2. इस मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 257/2001, थाना मडुआडीह, जिला वाराणसी में धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता के पास 2.5 ग्राम हेरोइन पाई गई थी।.....*
>
> *8. एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 और सीआरपीसी की धारा 4 और 5 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 19, 24 और 27-ए के तहत अपराधों को छोड़कर, सीआरपीसी में दिए गए जमानत के प्रावधान। लागू होगा। निःसंदेह अपराध भी संज्ञेय हैं और इस सीमा तक अधिनियम के प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर भी प्रभावी होंगे। इसलिए, जमानत के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होंगे।*
>
> *9. जमानती अपराधों को धारा 2 के खंड (ए) के तहत परिभाषित किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का अर्थ है ऐसे अपराध जो पहली अनुसूची में जमानती दर्शाए गए हैं या जो जमानत लागू होने के कारण किसी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाए गए हैं और "गैर-जमानती अपराध" का अर्थ है कोई अन्य अपराध। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में दो भाग हैं, पहला भाग भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के बारे में है और दूसरा भाग अन्य कानून के खिलाफ अपराधों के बारे में है। दूसरे*

भाग में यह प्रावधान है कि यदि अपराध तीन साल से कम कारावास या जुर्माने से दंडनीय है तो यह जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

10. उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, कथित अपराध एक जमानती अपराध है।"

18. ***स्टीफन म्यूएलर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 एससीसी ऑनलाइन बॉम 1974*** में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 10 और 11 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"10.. ...एनडीए की धारा 37 का शीर्षक या शीर्ष पीएस अधिनियम से पता चलता है कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा के मुख्य भाग में, विधानमंडल ने केवल यह घोषित किया है कि अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय होंगे, लेकिन विधानमंडल ने यह घोषित नहीं किया है कि अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे। केवल खंड (बी) में यह जमानत देते समय सीआरपीसी के तहत सीमाओं के अलावा जमानत देने की सीमाओं के बारे में बात करता है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों पर गौर करना होगा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध जमानती हैं या नहीं।

11. सीआरपीसी 1973 की पहली अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण के बारे में है। प्रत्येक अपराध के खिलाफ, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपराध संज्ञेय है या गैर-संज्ञेय, यह जमानती है या गैर-जमानती और यह किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अनुसूची का भाग I भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों से संबंधित है, जबकि भाग II अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। इसलिए, भाग II यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक होगा कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत अपराध जमानती हैं या नहीं। भाग II में, पहली प्रविष्टि यह प्रावधान करती है कि यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है, तो यह गैर-जमानती है। दूसरी प्रविष्टि के अनुसार, यदि अपराध 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है, तो यह भी गैर-जमानती है। तीसरी प्रविष्टि जो इस भाग में अंतिम प्रविष्टि है, यह घोषित करती है कि यदि अपराध 3 वर्ष से कम कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो यह जमानती और गैर-संज्ञेय है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत कई अपराध हैं जो 10 वर्ष तक के कारावास और 20 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं। कुछ ऐसे अपराध हैं जो 3 वर्ष से कम कारावास या जुर्माने से दंडनीय हैं। धारा 20(बी) (ii) (ए) और धारा 27 के तहत अपराध ऐसे अपराध हैं जो छह महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय हैं। इन अपराधों के लिए निर्धारित दंड के मद्देनजर, वे अनुसूची के भाग II में तीसरी प्रविष्टि में आते हैं और इसलिए, ये अपराध जमानतीय होंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 37(10(ए) घोषित करती है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध सीआरपीसी के प्रावधानों के बावजूद संज्ञेय हैं। यदि वह प्रावधान

नहीं होता, तो भाग II में वर्गीकरण के आधार पर ये अपराध असंज्ञेय होते, लेकिन धारा 37(1)(ए) के विशिष्ट प्रावधान द्वारा इन्हें संज्ञेय बनाया गया है।

19. ***राज कुमार बनाम राजस्थान राज्य 2019 एससीसी ऑनलाइन राज 5732, पैरा 8*** में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा,*"एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1) के आधार पर, अपराध संज्ञेय हो गया है, हालांकि, सूची में आइटम नंबर 3 के अनुसार (प्रथम अनुसूची के भाग II में) अपराध स्पष्ट रूप से जमानतीय है।"*

20. ***मुहम्मद नवास महमूद बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर, 2020 एससीसी ऑनलाइन केर 564, 6 फरवरी, 2020*** को तय, केरल उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 14 और 19 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"14. अधिनियम की धारा 22 (ए) के तहत अपराध एक वर्ष तक के कठोर कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) ए के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा भी वही है। यह इस प्रकार है कि संहिता की पहली अनुसूची के भाग II में अंतिम प्रविष्टि के अनुसार, उपरोक्त अपराध जमानत योग्य हैं।

19. संहिता की धारा 436 (1) के तहत जमानत का दावा करने का अधिकार एक पूर्ण और अप्रतिबंधित अधिकार है। जमानती अपराधों में, जमानत देने में विवेक का कोई सवाल नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानती अपराध में जमानत का दावा आरोपी द्वारा अधिकार के रूप में किया जा सकता है। जब तक अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, न्यायालय जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के

लिए बाध्य है (देखें रसिकलाल बनाम किशोर : (2009) 4 एससीसी 446 : एआईआर 2009 एससी 1341 और तालाब हाजी हुसैन बनाम मधुकर पुरुषोत्तम मांडकर : एआईआर 1958 एससी 376) जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को केवल संहिता की धारा 436 (2) में उल्लिखित परिस्थितियों में ही जमानत देने से इनकार किया जा सकता है (देखें विल्सन बनाम केरल राज्य : 2011 (2) केएचसी 129 : 2011 (2) केएलटी 596)।

21. इसके अलावा, 18.12.2024 के एक हालिया फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ***कुलदीप सिंह उर्फ कीपा बनाम पंजाब राज्य*** के मामले में पैराग्राफ 80 और 81 में निम्नानुसार माना:

"80. स्पष्ट विधायी स्पष्टीकरण के अभाव में, न्यायपालिका के लिए उपलब्ध एकमात्र व्यवहार्य उपाय बीएनएसएस 2023 की अनुसूची II पर व्याख्यात्मक निर्भरता है, जो निर्धारित सजा के आधार पर अपराधों के वर्गीकरण को चित्रित करती है। इस अनुसूची के अंतिम कॉलम के अनुसार, तीन साल से कम की सजा वाले अपराधों को स्पष्ट रूप से गैर-संज्ञेय और जमानती के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, एनडीपीएस अधिनियम के ढांचे के भीतर, अपराधों को स्पष्ट रूप से द्वितीय अनुसूची के संगत कॉलम में संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नतीजतन, 'गैर-संज्ञेय' का पदनाम एनडीपीएस अपराधों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि अधिनियम एक विशेष कानून के रूप में संचालित होता है, जिसका प्रभाव सर्वोपरि है।

81. फिर भी, जबकि एनडीपीएस अधिनियम ऐसे अपराधों को स्पष्ट रूप से संज्ञेय घोषित करता है, यह उनकी जमानतीयता पर चुप रहता है। इस विधायी चूक के मद्देनजर, विधानमंडल के इरादे को बीएनएसएस 2023 की अनुसूची II के माध्यम से समझा जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि तीन साल से कम की सजा वाले सभी अपराधों को जमानतीय माना जाएगा। चूंकि एनडीपीएस अधिनियम के तहत कम मात्रा में मादक पदार्थ से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम सजा एक वर्ष है, इसलिए तार्किक रूप से यह माना जाता है कि इस तरह के अपराध को मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत जमानती माना जाना चाहिए।

22. हाल ही में, ***बिलाल हुसैन बनाम असम राज्य*** के मामले में 03.01.2025 के आदेश द्वारा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पैराग्राफ 17 और 18 में निम्नानुसार माना:

"17. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों को विशेष कानून में इसके विपरीत किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अधीन बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, चूंकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं है कि उक्त अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे, इसलिए, यह प्रश्न कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कौन से अपराध

जमानती हैं और कौन से गैर-जमानती हैं, इसका उत्तर केवल बीएनएसएस 2023 में निहित सामान्य प्रावधानों की सहायता से ही दिया जा सकता है। बीएनएसएस के सामान्य प्रावधान किसी भी विशेष कानून के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जब तक कि विशेष कानून उस संबंध में कोई विशेष प्रावधान न करे।

18. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि, बीएनएसएस, 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में यह प्रावधान है कि यदि अपराध 3 वर्ष से कम कारावास और जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो उसे जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उक्त अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है, बीएनएसएस, 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में दिए गए सामान्य प्रावधान एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों के लिए भी लागू होंगे। तदनुसार, यह माना जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21 (ए) के तहत अपराध, जो 3 साल से कम की सजा का प्रावधान करता है, एक जमानती अपराध है।"

23. एन.डी.पी.एस. अधिनियम और बी.एन.एस.एस., 2023 के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और साथ ही विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों की गहन जांच के बाद, यह न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत *छोटी मात्रा* से जुड़े अपराध जमानती हैं। इस विशिष्ट मुद्दे पर वैधानिक चुप्पी को देखते

हुए, और बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 4 और 5 के व्यापक अध्ययन के बाद, यह स्पष्ट है कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों को बी.एन.एस.एस., 2023 के प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुसार निपटाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि विशेष कानून स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रावधान करता है। बी.एन.एस.एस., 2023 मुख्य रूप से निर्धारित दंड की गंभीरता के आधार पर अपराधों के वर्गीकरण की रूपरेखा तैयार करता है। यह ध्यान रखना उचित है कि बीएनएसएस, 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में यह प्रावधान है कि *तीन वर्ष से कम* कारावास या *केवल जुर्माने* से दंडनीय कोई भी अपराध जमानती अपराध माना जाएगा। चूंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत कम मात्रा में प्रतिबंधित सामान से जुड़े अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की सजा हो सकती है, इसलिए तार्किक और कानूनी रूप से यह माना जा सकता है कि ऐसा अपराध बीएनएसएस, 2023 के तहत वर्गीकरण के अनुसार जमानती अपराध के दायरे में आता है। इसलिए, एन.डी.पी.एस. अधिनियम में *सभी* अपराधों को गैर-जमानती घोषित करने वाले स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, बीएनएसएस, 2023 की पहली अनुसूची के भाग II में निर्धारित सामान्य प्रावधान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू होंगे। यह निर्माण विधायी मंशा को कायम रखता है और विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के प्रक्रियात्मक उपचार में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

24. ***मुहम्मद नवास महमूद बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर (सुप्रा)*** में, जिसमें न्यायालय ने अधिकारपूर्वक टिप्पणी की थी कि जमानती अपराध के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436(1) के तहत जमानत का दावा करने का अधिकार पूर्ण, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि जमानती अपराधों के मामले में जमानत देना न्यायिक विवेक का मामला नहीं बल्कि एक वैधानिक आदेश है। इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं है कि जमानती

अपराधों में, कोई आरोपी व्यक्ति बिना किसी असाधारण आधार या परिस्थितियों को स्थापित किए, अधिकार के रूप में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह न्यायालय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुविचारित दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत है। कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है - जब किसी अपराध को जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते कि वह अपेक्षित जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत करे, जैसा कि निर्देश दिया जा सकता है। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी औपचारिक जमानत आवेदन की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे मामलों में जमानत देने से इनकार करना प्रक्रियात्मक कानून के तहत निहित वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होगा। इसलिए, एनडीपीएस की धारा 21(ए) के तहत कम मात्रा से जुड़े अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति। अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को बीएनएसएस, 2023 की धारा 478(1) के प्रावधानों के अनुसार कानून के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर तत्काल जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

25. इस प्रकार, यह न्यायालय स्पष्ट रूप से मानता है कि *स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985* की धारा 21(ए) के तहत अपराध, जिसमें एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा निर्धारित है, को 'जमानती अपराध' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार, जहां एनडीपीएस अधिनियम के तहत उल्लंघन में संबंधित अधिसूचना के अनुसार मादक दवाओं या मनप्रभावी पदार्थों की 'छोटी मात्रा' शामिल है, ऐसे अपराधों को प्रकृति में 'जमानती' माना जाएगा। जमानती अपराध के मामले में, जमानत का अधिकार वैधानिक अधिकार का मामला है और ऐसी परिस्थिति में, पुलिस या स्वयं न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त को गिरफ्तारी के पश्चात स्वतः जमानत पर

रिहा किया जा सकता है, बशर्ते कि वह अपेक्षित जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत करे, जैसा कि निर्देश दिया जा सकता है।

26. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति बिहार राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच प्रसारित करने के लिए सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को परिचालित करें, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन हो सके।

27. इसके अतिरिक्त, आदेश की एक प्रति बिहार के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी जाए, जो राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देंगे तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश और निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया जाता है कि जहां बरामद प्रतिबंधित पदार्थ कम मात्रा में है, वहां अपराध जमानत योग्य है और संदिग्ध व्यक्ति जमानत का हकदार है।

28. मामले से अलग होने से पहले, मैं विद्वान न्यायमित्र श्रीमती वैष्णवी सिंह द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करता हूं।

29. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह श्रीमती वैष्णवी सिंह, विद्वान न्यायमित्र, आपराधिक विविध संख्या 15800/2025 को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित शुल्क के रूप में 7,000 (सात हजार रुपये) का भुगतान करें।

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पंकज/एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।